P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समन्वित कृषि विकास एवं प्रादेशिक नियोजन–जनपद मेरठ का एक भौगोलिक विश्लेषण

Integrated Agricultural Development and Regional Planning - A Geographical Analysis of District Meerut

Paper Submission: 14/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

धनबीर सिंह
शोधार्थी,
भूगोल विभाग,
दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत
बागपत, उ०प्र०, भारत

सारांश

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख आधार है। यह लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है कृषि का समन्वित विकास मुख्य रूप से बहुउद्देशीय कृषि आधारित उद्योग–धन्धों पर निर्भर करता है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधनों का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याऐं उत्पन्न हो गयी हैं। हरित क्रांति के पश्चात यद्यपि खाद्यान्न उत्पादन में तीव्रगति से वृद्धि हु ई है, परन्तु पर्यावरणीय समस्याऐं भी उत्पन्न हो गयी हैं। कृषि में निवेश का अभाव इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बन गया है। कृषि आधारित उद्योग–धन्धों को विकसित कर इसके पिछड़ेपन को न केवल दूर किया जा सकता है, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की जा सकती है। क्षेत्रीय विषमता को कम करने हेतु कृषि का समन्वित विकास किया जाना अपेक्षित है।

Agriculture is the mainstay of the development of the rural economy. It provides direct and indirect employment to about 70 percent of the rural population. The integrated development of agriculture depends mainly on multipurpose agro-based industries. At the rural level, the means of employment are becoming increasingly depressed, due to which problems like poverty, unemployment and migration have arisen. Although the production of food grains has increased rapidly since the Green Revolution, environmental problems have also arisen. Lack of investment in agriculture has become a major reason for backwardness of the region. By developing agro-based industries, its backwardness can not only be overcome, but employment opportunities can also be increased. A coordinated development of agriculture is required to reduce regional disparities.

मुख्य शब्द : कृषि, विकास, समन्वित, तकनीकी, सेवाऐं, नियोजन।
Agriculture, Development, Integrated, Technical, Services, Planning.

प्रस्तावना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख आधार कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। इसका विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। कृषि में निवेश का अभाव, तकनीकी, कृषि सेवाओं तथा वित्त का अभाव कृषि विकास में बाधक बना हुआ हैं। समन्वित कृषि विकास न केवल कृषि विकास का प्रमुख आधार है, बल्कि द्वितीयक क्षेत्र को गति प्रदान करने का साधन है। कृषि आधारित उद्योग–धन्धों के पतन ने कृषि के विकास को अवरूद्ध कर दिया है। इसी कारण ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी तथा पलायन जैसी समस्याऐं उत्पन्न हो गयी हैं। यातायात एवं परिवहन सुविधाओं का पिछड़ापन तथा कृषि बाजारों का अभाव कृषकों को कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य प्रदान कराते हैं क्योकि मध्यस्थ कृषकों से कृषि उपज को स्थानीय स्तर पर क्रय करके कृषि बाजारों में उच्च दर पर विक्रय करते है। जिससे मध्यस्थलों को कृषकों से अधिक मुनाफा प्राप्त होता है।

समन्वित कृषि विकास के द्वारा न केवल कृषि उत्पादन मे वृद्धि किया जाना संभव है, बल्कि उससे अन्य उद्योग–धन्धों को विकसित किया जाना

अपेक्षित है। इसमें फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन कर दीर्घकालिक एवं सन्तुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इस कृषि के माध्यम से

ग्रामीण स्तर पर न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी बल्कि गरीबी तथा पलायन जैसी समस्या का भी समाधान हो सकेगा। ग्रामीण स्तर पर प्रचलित पुरानी कृषि पद्धति उत्पादन तथा उत्पादकता दोनो को प्रभावित करती है। जिसके कारण कृषकों की आय न्यूनतम है तथा वह अक्सर कर्ज के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। कृषि के साथ–साथ अन्य कार्यो के अभाव के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नही है। गरीबी तथा ऋण ग्रहस्तता के कारण कृषक आये दिन आत्म हत्या कर रहे है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु मेरठ जनपद का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित मेरठ जनपद एक विकसित जिला है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति $28^{o}57–29^{o}02$ उत्तरी अक्षांश से $77^{o}40–77^{o}45$ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। यह जनपद उत्तर में मुज्जफ्फरनगर जनपद, पश्चिम में शामली, दक्षिण–पश्चिम में बागपत तथा गाजियाबाद जनपद तथा दक्षिण में हापुड़ तथा बुलन्दशहर जनपद अवस्थित हैं। इसकी पूर्वी सीमा पर अमरोहा तथा बिजनौर जनपद अवस्थित हैं। इस जनपद की पूर्वी सीमा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है। जबकि पश्चिमी सीमा पर हिण्डन नदी अवस्थित है यह हिण्डन व गंगा नदी के दोआब में अवस्थित है। वर्ष 2011 के अनुसार इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2590 वर्ग किमी है, जिसमें 2345.11 वर्ग किमी० ग्रामीण तथा 244.89 वर्ग किमी० नगरीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। वर्ष 2011 के अनुसार यहां पर कुल 667 गांव, 3 तहसील तथा 12 विकास खण्ड सम्मिलित है। वर्ष 2011 के अनुसार मेरठ जनपद की कुल जनसंख्या 34.43 लाख है, जिसमें 16.84 लाख ग्रामीण तथा 17.59 लाख नगरीय जनसंख्या सम्मिलित है। यहां कुल साक्षरता 70.75 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता 80.81 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 59.41 प्रतिशत है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कृषि सुविधाओं की उपलब्धता तथा उन पर जनसंख्या की निर्भरता का विश्लेषण करना।
2. फसलों के उत्पादन तथा प्रतिरूप को ज्ञात करना।
3. कृषि विकास में बाधक भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पनाऐं

1. अध्ययन क्षेत्र में कृषि सुविधाऐं जनसंख्या के अनुपात मे उपलब्ध है।
2. तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या ने कृषि भूमि उपयोग तथा फसल प्रतिरूप को प्रभावित किया है।
3. कृषि का उच्च विकास प्राकृतिक मानवीय तथा तकनीकी कारकों पर निर्भर करता है।

शोध विधि तन्त्र

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े प्रश्नावली अनुसूची तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि से क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर प्राप्त किये गये है। द्वितीयक आंकड़े जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ से प्राप्त किये गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं के स्तर तथा प्रतिरूप को प्राप्त करने हेतु विविध सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के प्रदर्शन तथा विश्लेषण हेतु सारणीयन तथा वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

सेम्पल

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु कुल 200 सेम्पल लिये गये है। इन सेम्पलों को चयनित किये गये 10 गांवों से प्राप्त किया गया है। प्रत्येक गांव से 20 सेम्पल यादृच्छिक विधि द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु कृषि विकास तथा समन्वित कृषि विकास से समन्वित कुछ शोध कार्यो का अवलोकन किया गया है अवलोकन किये गये पूर्व शोध साहित्य को निम्न प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

जी०एस० भल्ला (2001)[1] ने अपने शोध में पाया कि 1960 के पश्चात कृषि विकास में उन्नत किस्म के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है घोष (2003)[2] ने अपने शोध पत्र में पाया कि कृषि में रोजगार की दर में 2.08 प्रतिशत वार्षिक की कमी 1987–88 से 1993–94 की अवधि में हुई है। यह 1993–94 से 1999–2000 की अवधि में 0.8 प्रतिशत रोजगार के अवसर कृषि में कम हुए हैं। कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग से फार्म श्रमिको की संख्या में कमी आई है। कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। मेहता (2004)[3] ने अपने शोध में पाया कि भारतीय अर्थव्यस्था में कृषि संरचना का स्वरूप बदल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्मा (2006)[4] ने अपने शोध में विश्लेषित किया कि पंजाब राज्य में कृषि मजदूरों का प्रतिरूप परिवर्तित हुआ है। स्थानीय कृषि मजदूरों का रोजगार के अभाव में पलायन प्रारम्भ हो गया है। अहमद (2008)[5] ने कृषि विकास मे तकनीकी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। तकनीकी के अभाव मे कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जाना संभव नही है। खान (2009)[6] ने कृषि के समन्वित विकास हेतु कृषि के साथ–साथ पशुपालन को वरीयता प्रदान करने पर बल दिया। पशुपालन कृषकों को अतिरिक्त आय प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रीवास्तव (2010)[7] ने अपने शोध में पाया है कि कृषि के विकास हेतु कृषि तकनीकी का प्रयोग मुख्य रूप से बड़े कृषि फार्मों पर अधिक सफल रहा है, जबकि छोटे फार्म पर तकनीकी का प्रयोग ज्यादा सफल नही हैं। सिद्दकी (2011)[8] ने तकनीकी एवं कृषि विकास का स्तर नामक शीर्षक पर शोध में पाया कि उच्च कृषि सुविधाओं से सम्पन्न क्षेत्र में कृषि विकास का स्तर अति उच्च पाया जाता है, जबकि कृषि सुविधाओं की

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समस्या से ग्रहस्त क्षेत्र में कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। खान एवं रहमान (2012)[9] ने कृषि एवं पशुपालन के विकास में तकनीकी के साथ–साथ वायुमण्डलीय दशाओं का अनुकूल होना अति महत्वपूर्ण होता है। दीवन (2012)[10] ने सत्त विकास तथा कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया है। इन्होंने अपने शोध में पाया कि कृषि का सतत एवं सन्तुलित विकास कृषि तकनीकी पर निर्भर अवश्य करता है, परन्तु रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण कर कृषि में सत्तता प्राप्त की जा सकती है। इकबाल (2012)[11] ने अपने शोध में पाया कि कृषि का विकास लघु एवं सीमान्त कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। इन्होंने लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास मे पशुपालन की भूमिका को स्पष्ट किया। पशुपालन ने कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। मिश्रा एवं सरकार (2013)[12] ने कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर के मापन तथा वृद्धि हेतु सुझाव प्रस्तुत किये। कृषि का सर्वांगीण विकास तभी संभव हो सकता है जब प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। कुमार (2015)[13] ने अपने शोध में कृषि विकास में विविधता का अध्ययन कर उनके कारणों को ज्ञात किया तथा कृषि विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल्यांकन किया। दास (2015)[14] ने अपने शोध में पाया कि सहकारिता का योगदान ग्रामीण विकास में अति महत्वपूर्ण है। सहकारिता का विकास कृषि एवं अर्थव्यवस्था को विकासित करने में सहायक है। कुमार (2016)[15] ने अपने शोध में कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग–धन्धें का मूल्यांकन किया। इन्होने पाया कि ग्रामीण आर्थिक विकास में कृषि आधारित उद्योग–धन्धें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्रदान करते हैं तथा गरीबी व पलायन जैसी समस्या को कम करने में सहायक हैं।

फसल प्रतिरूप

फसल प्रतिरूप से तात्पर्य विविध फसलों के अन्तर्गत संलग्न क्षेत्रफल से है। किसी भी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप वहां की जलवायु, धरातलीय संरचना, तथा सिंचाई के साधनों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ कृषि विकास के कारक व तकनीकी इसकों प्रभावित करती है। इसके साथ ही फसल प्रतिरूप जनसंख्या की आवश्यकतानुसार परिवर्तनशील है। फसल प्रतिरूप का परिवर्तन वर्तमान समय की आवश्यकता है क्योकि खाद्यान्न, दलहन तथा तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में काफी विविधता मिलती है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता क्षमता प्रभावित होती है। फसल प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया गया है–

$$CP = \frac{Ca\ ,\ Cb\ ,\ Cc\ ------------\ Cr}{N_1,\ N_2,\ N_3\ ------------\ N} \times 100$$

Where,
CP = cropping pattern
Ca, Cb, Cc, ... Cr = Agriculture land which is used in the various crops
N = Total cultivated Land

सारणी–1
जनपद मेरठ की मुख्य फसलों का प्रतिरूप, वर्ष 2018

क्र०सं०	फसल	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	चावल	16090	7.31
2.	गेहूँ	68497	31.10
3.	जौं	101	0.05
4.	बाजरा	23	0.01
5.	मक्का	346	0.16
6.	मूंग	91	0.04
7.	मसूर	396	0.18
8.	चना	8	0.01
9.	मटर	147	0.06
10.	अरहर	815	0.37
11.	उड़द	1194	0.54
12.	सरसों	5415	2.46
13.	गन्ना	121936	55.37
14.	आलू	5075	2.30
15.	प्याज	80	0.04
योग		**2202144**	**100**

स्रोतः जिला सांख्यिकी पत्रिका, जनपद मेरठ, वर्ष 2018

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहां पर सर्वाधिक 55.37 प्रतिशत भू–भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है, जबकि 31.10 प्रतिशत भाग पर गेहूँ तथा 7.31 प्रतिशत भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यहां पर खाद्यान्न फसलों के अन्तर्गत कुल 38. 63 प्रतिशत भाग सम्मिलित है, जबकि दलहन फसलों के अन्तर्गत 1.20 प्रतिशत तथा तिलहन के अन्तर्गत 2.46 प्रतिशत भाग सम्मिलित है,। शेष भाग 57.46 प्रतिशत भाग पर गन्ना, आलू तथा प्याज का उत्पादन किया जाता है।

उपरोक्त फसलों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यहां पर गन्ना गेहूँ तथा चावल मुख्य फसलें है, जिनकी कृषि सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है।

कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन से तात्पर्य प्रति हेक्टेयर फसलों के उत्पादन से है। कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसका प्रमुख कारण कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। कृषि में उत्पादन बढ़ने के कारण न केवल जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति हो सकी है, बल्कि उद्योग–धन्धों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त हुआ है। इसी कारण उद्योगों का विकास संभव हो सका है। द्वितीयक श्रेणी के क्रिया कलापों में वृद्धि होने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–2
जनपद मेरठ में प्रमुख फसलों का उत्पादन (कुन्तल प्रति हेक्टेयर में)
(वर्ष 1990–91 से 2017–18)

क्र० सं०	फसल	उत्पादन (कुन्तल प्रति हेक्टेयर में)				
		2017–18	2010–11	2000–01	1990–91	परिवर्तन 1990–91 से 2017–18
1	चावल	58.62	21.90	22.62	39.70	18.92
2	गेहूँ	43.65	40.73	36.17	33.88	9.77
3	जौं	39.60	33.92	32.35	32.20	7.42
4	बाजरा	19.54	18.49	12.82	12.48	7.06
5	मक्का	76.96	17.93	19.90	24.45	52.51
6	उड़द	15.22	6.37	4.91	10.31	4.91
7	मूंग	12.01	6.22	3.95	9.90	2.11
8	मसूर	10.29	7.05	6.26	7.24	5.05
9	चना	10.48	8.76	8.53	11.88	–1.40
10	मटर	14.69	11.59	10.32	15.89	–1.20
11	अरहर	16.61	6.68	7.77	10.25	6.36
12	सरसों	14.19	11.94	12.26	8.55	5.64
13	गन्ना	953.84	659.96	617.84	643.04	310.80
14	आलू	344.28	191.28	216.17	224.36	119.92

स्रोतः जिला सांख्यिकी पत्रिका, जनपद मेरठ, वर्ष 1991, 2001, 2011 व 2019

उपरोक्त सारणी के अनुसार अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 1990–91 से 2017–18 की अवधि मे गैहुँ का उत्पादन 9.77 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, चावल 18.92 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, जौ 7.42 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, बाजरा 7.06 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, मक्का 52.51 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, उडद 4.91 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, मूंग 2.11 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, मसूर 5.05 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, अरहर 6.56 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, सरसों 5.64 कुन्तल प्रति हेक्टेयर, गन्ना 310.80 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा आलू 119.92 कुन्तल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मे वृद्धि हुई है। चना 1.40 तथा मटर 1.20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हुआ है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक मक्का 76.96 कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुआ है।

कृषि उत्पादकता

भारत में कृषि उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है। यहां पर कम उत्पादकता का प्रमुख कारण उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, कृषि जोतो का छोटा आकार, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उन्नत कृषि यन्त्रों का अभाव तथा वित्त का अभाव इत्यादि हैं। अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में कृषि उत्पादकता के वितरण प्रतिरूप को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

सारणी–3
जनपद मेरठ में कृषि उत्पादकता का वितरण प्रतिरूप, वर्ष 2018

क्र०सं०	श्रेणी	उत्पादकता	विकासखण्ड
1.	अति उच्च	164.30–171.83	मेरठ
2.	उच्च	156.77–164.30	–
3.	मध्यम	149.29–156.77	खरखौदा
4.	निम्न	141.71–149.29	माछरा, रोहटा, जॉनीखुर्द, रजपुरा
5.	अतिनिम्न	134.18–141.71	सरूरपुर खुर्द, सरधना, दौराला, मवाना, हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़

स्रोतः जिला सांख्यिकी पत्रिका जनपद मेरठ वर्ष 2018

अध्ययन क्षेत्र जनपद मेरठ में औसत कृषि उत्पादकता 142.82 है। यहां पर सर्वोच्च कृषि उत्पादकता 171.83 मेरठ विकासखण्ड तथा सबसें कम 134.18 दौराला विकासखण्ड में है। सरूरपुर खुर्द 135.08, सरधना 137.22, दौराला 134.18, मवाना 138.62, हस्तिनापुर 134.80 तथा परीक्षितगढ़ 138.10, में कृषि उत्पादकता अतिनिम्न है।

यहां पर निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, वित्त का अभाव, जोतों का छोटा आकार तथा यातायात एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यहां पर कृषि तथा पशुपालन की अपार संभावनाऐं हैं। कृषि उपज पर उद्योग–धन्धों को विकसित कर न केवल कृषि को विकसित किया जा सकता है बल्कि बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर पलायन व गरीबी की समस्या को भी कम किया जा सकता है। यातायात एवं परिवहन की सुविधाओं का अभाव कृषि विकास में बाधक है। वित्त की सुविधाओं के विकसित न होने के कारण कृषक साहूकारों से उच्च व्याज दर पर ऋण प्राप्त करते है, जिसके कारण वह कर्ज के बोझ में दबंकर आत्म हत्या कर लेते है। कृषि उपज का निम्न मूल्य प्राप्त होने के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार नही हो पा रहा है। यद्यपि कृषि में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग हो रहा है परन्तु केवल बड़े कृषक ही इसका फायदा उठा पा रहे है। जबकि छोटे कृषकों को अनुदान व कृषि सहायता का कोई लाभ नही प्राप्त हो पा रहा है।

सुझाव

समन्वित कृषि विकास हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं–

1. कृषि उपज पर आधारित उद्योग–धन्धों को ग्रामीण स्तर पर स्थापित किया जाये जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेगें।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन सुविधाओं को विकसित कर कृषि उपज को नगर तथा मण्डियों में बेचने के लिए मार्ग प्रसस्त किया जाये।
3. कृषकों को कृषि तथा उद्योग–धन्धें विकसित करने हेतु रियायती दर पर वित्त की सुविधा प्रदान की जाये।
4. कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग कर न केवल मृदा को अनुर्वर होने से बचाया जा सकता है, बल्कि मिट्टी को लम्बी अवधि तक उपजाऊ बनाये रखा जा सकता है।
5. खाद्यान्न फसलों के स्थान पर कृषक हार्टीकल्चर को वरीयता प्रदान कर अधिक लाभांश प्राप्त कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *Bhalla, G.S. (2001), "Indian Agriculture : Four Decades of Development", New Delhi, Thousand Oaks, Lender, pp. 1-2.*
2. *Ghos, J. (2003), "Whatever Happened to Farm Employment", Frontline, Vol. 20, Issue 10.*
3. *Mehta, J. (2004), "Changing Agrarian Structure in Indian Economy".*
4. *Verma, A.K. (2006), "Pattern of Wages and Loans Among Migrant and Local Agricultural Labourers to Punjab", Journal of Agricultural Development and Policy, January-December, pp. 141.*
5. *Ahmad, M. (2008), "Impact of Technology on the Development of Agriculture in Uttarakhand", The Geographer, Vol. 55, No. 1.*
6. *Khan, N. (2009), "Livestock Husbandry Rural Workforce and Employment Generation : A Case Study", The Geographer, Vol. 56, No. 2.*
7. *Shrivastava, S. (2010), "Adoption of Farm Technology and Agricultural Development", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 40, No. 2.*
8. *Shiddiqui, S.H. (2011), "Technology and Level of Agricultural Development in Aligarh District", The Geographer, Vol. 58, No. 2.*
9. *Khan, N. and Rehman, A. (2012), "Pattern of Livestock Husbandry in Mahamaya Nagar", The Geographer, Vol. 59, No. 1.*
10. *Divan, R. (2012), "Sustainable Development Innovation in Agricultural Land Use : A Case Study of Gumla District", Journal of Integrated Development and Research, Vol. 2, No. 2, pp. 34-39.*
11. *Iqbal, M.A. (2012), "Role of Animal Husbandry on Socio-Economic Development of Marginal and Small Farmers in Aligarh District", Ph.D. Thesis, AMU, Aligarh, pp. 230-243.*
12. *Mishra, S.P. and Sarkar, S. (2013), "Agricultural Productivity and Levels of Agricultural Development in Chandauli District, U.P.", National Geographical Journal of India, Vol. 59, Issue 2, June, pp. 51-62.*
13. *Kumar, M.P. (2015), "Disparities in Agricultural Development of Uttar Pradesh : An Inter District Study", Indian Journal of Regional Science, Vol. 53, No. 2, pp. 141-156.*
14. *Das, C. (2015), "Co-Operative Based Economic Development in Phulia", IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 20, Issue 9, pp. 133-139.*
15. *Kumar, Suresh (2016), "Role of Agro-Industries in Rural Employment – A Geographical Study of Block Joya", District Amroha, Remarking An Analisation, Vol. I, Issue V, August, pp. 30-32.*